चार साल का एक लड़का बिना किसी की मदद के सर्फबोर्ड पर समुद्री लहरों पर सवारी कर लेता है। ब्राज़ील के जोआओ विटोर को सर्फिंग की प्रेरणा अपने पिता व बड़ी बहन से मिली हैं। जब वह सिर्फ दो साल का था तब अपने आप सर्फबोर्ड पर खड़े होकर उसने अपने माता-पिता को हैरान कर दिया। जोआओ की मां कमिला ने बताया कि जोआओ के पिता व बड़ी बहन मारिया ने उसका परिचय इस खेल से करवाया है। उन्होंने बतायाः ''मेरे पति मारिया को अक्सर लहरों में धकेल देते थे, उस समय जोआओ उनकी गोद में हुआ करता था। एक दिन उसने भी अपनी बहन की तरह लहरों के साथ खेलने की जिद की और जब मेरे पति ने उसे लहरों में छोड़ा तो उन्होंने देखा कि जोआओ लहरों के बीच बिल्कुल सहज था।'' इतनी कम उम्र के बच्चे को इतनी जल्दी इस खेल में महारत हासिल करते देखकर उसके माता-पिता हैरान हैं। कमिला ने कहा ''जब वह पहली बार सर्फबोर्ड पर खड़ा हुआ तो हमें यकीन नहीं हुआ क्योंकि उस समय वो बहुत ही छोटा था।''

डॉ. जाधव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चीन से डेटा चोरी के खिलाफ चेताया था

जानेमाने इकॉनमिस्ट डॉ. जाधव ने 2018 में राज्यसभा में कहा था कि वित्तीय निवेश के मामलों में चीन को फ्री हैन्ड छोड़ना भारतीयों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है

- डॉ. जाधव 2009 से 2014 तक पुणे युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, उन्होंने तब राज्यसभा में कहा था कि चीन की मल्टीनैशनल कम्पनियों को भारत में बैंकिंग व नॉन बैंकिंग फाइनैंस सैक्टर में निवेश के लिए खुली छूट देना चीन को भारतीयों का डेटा चोरी करने के लिए पूरी तरह से आतुर कर देगा।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। अर्थशास्त्री एवं वर्ष 2016 से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य डॉ. नरेन्द्र जाधव (67) चीन को देश के वित्तीय क्षेत्र में घुसपैठ की खुली छूट देने के बारे में 26 जुलाई 2018 को सदन में चेतावनी देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष इसे एक खतरा बताते हुए कहा था कि इसके परिणामस्वरूप भारतीयों के डेटा पर बड़े पैमाने पर निगाह रखी जा सकती है।

वर्ष 2009 से 2014 तक पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे व उसके बाद दो वर्ष तक योजना आयोग के सदस्य रह चुके डॉ. जाधव ने तब भारत की नॉन-बैंकिंग कंपनियों में चीन की मल्टी-नैशनल फर्म्स में निवेश करने और इसके जरिए भारत के फायनैंशियल सैक्टर में प्रवेश करने को लेकर खतरे की चेतावनी दी थी। उनकी मुख्य चिन्ता इसको लेकर थी कि अलीबाबा जैसी चीन की कंपनियां पेटीएम जैसी भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी खरीद रही है और यदि चीन की इन कंपनियों को देश के एन.बी.एफ.सी. सैक्टर (नॉन बैंकिंग फायनैन्शियल कंपनीज़ सैक्टर) पर हावी होने की अनुमति दी जाती है तो इससे सेवाओं का मूल्य इतना सस्ता हो जाएगा कि अन्य कंपनियों के पास बाजार से बाहर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के अलावा राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद सहित कम से कम 10 केन्द्रीय मंत्री और अशोक गहलोत, अमरिन्दर सिंह और शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्रियों के व्यक्तिगत व वित्तीय डेटा तक चीन की सॉफ्टवेयर कंपनी की पहुंच के खुलासे के बाद उनकी चेतावनी सही साबित हो रही है।

जाधव की चिन्ता का कारण अलीबाबा द्वारा भारतीय फर्म पेटीएम में हिस्सेदारी खरीदना और फिर वर्ष 2017 में पेटीएम का मुम्बई की फर्म क्रेडिटमेट में हिस्सेदारी खरीदना था।

क्रेडिटमेट एन.बी.एफ.सी. सैक्टर के साथ ही कई बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनियों को सेवाएं प्रदान करती है। बताया गया था कि अलीबाबा ग्रुप आदित्य बिड़ला ग्रुप के साथ अपने टाई-अप के जरिए उसकी एन.बी.एफ.सी. शाखाओं आई.डी.एफ. सी. बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक की वित्तीय मदद कर रहा था।

इस अर्थशास्त्री ने राज्यसभा में जोर देकर कहा था कि भारत को अपने प्राइवेट बैंकों में निवेश प्रतिबंधों को लागू कर एन.बी.एफ.सी. सैक्टर में विदेशी भागीदारी को अवश्य रोकना चाहिए। पार्लियामैन्टरी पैनल ऑफ फायनैन्स में भी उन्होंने एन.बी.एफ.सी. सैक्टर में विदेशी भागीदारी का मुद्दा उठाया था।

डॉ. जाधव ने तब तर्क दिया था कि भारतीयों के निजी और व्यक्तिगत डेटा विदेशी कंपनियों के हाथ लग सकते हैं और खासतौर पर चीन की कंपनियों के, और विदेशी स्वामित्व के संबंध में प्राइवेट और एन.बी.एफ.सी. कंपनियों को समान असर दिया जाना अपेक्षित है।

वे कहते हैं कि सिर्फ पेटीएम के ही जरिए चीन की सरकार करोड़ों भारतीयों और यहां के कॉर्पोरेशन्स के व्यक्तिगत और वितीय डेटा तक अपनी पहुंच बना सकती हैं। चीन के लोगों के पास भारी मात्रा में धन है और वे इस धन को हमारे बाजारों में लगातार वस्तुओं और मूल्यों को इतना कम कर सकते हैं कि उनके अलावा बाजार में कोई कंपनी नहीं टिक सकती।

जब उनसे यह पूछा गया कि भारत भी बदले की कार्यवाही कर चीन की एन.बी.एफ.सी. कंपनियों पर अपना नियंत्रण क्यों नहीं स्थापित कर लेता, तब उन्होंने ध्यान दिलाया कि यह संभव नहीं है क्योंकि चीन इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मिल रही चुनौती के रूप में देखता है। "डॉनल्ड ट्रम्प सरकार क्यों चीन के मोबाइल्स को अमेरिका में प्रतिबन्धित करना चाहती है? क्योंकि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।"

वे स्पष्ट करते हैं कि सरकार इस पर किस तरह कार्यवाही कर सकती है। "वर्तमान कुछ शर्तों पर प्राइवेट बैंक लायसैन्स दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्राइवेट बैंक शुरु करने के लिए, इसमें कम से कम 26 प्रतिशत स्वामित्व भारतीयों का होना चाहिए और किसी भी निवेशक की बैंक में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। मैंने प्रस्ताव दिया था कि इसी तरह के प्रतिबन्ध एन.बी.एफ.सी. कम्पनियों पर भी लगाने चाहिए।" उनका दुःख यह है कि सरकार ने उनकी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इसी भाजपा सरकार ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था।

चीन ने भारी पूंजी इन्वैस्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चीनी निवेश 1600 से ज्यादा भारतीय कम्पनियों में हुआ है। ठाकुर ने इन भारतीय फर्मों तथा चीनी निवेशकों की भी जानकारी दी। चीनी निवेश हासिल करने वाले दो निजी बैंक भी हैं- आई.सी.आई.सी.आई. (फनी किरन से) तथा ऐक्सिस बैंक। चीनी निवेश की सर्वाधिक मात्रा, 17.20 करोड़ डॉलर भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में है, इसके बाद 15.119 करोड़ डॉलर पुस्तक प्रकाशन में, 14.425 करोड़ डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तथा 13.965 करोड़ डॉलर का निवेश सेवा-क्षेत्र में हुआ है। जिसमें बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय व्यवसाय, आर एंड डी तथा कूरियर सेवाएं शामिल हैं।

अन्य बड़े चीनी निवेशों में शामिल हैं- 11.988 करोड़ डॉलर बिजली उपकरण क्षेत्र में, 6.611 करोड़ डॉलर ट्रेडिंग में, 3.393 करोड़ डॉलर गैर परम्परागत ऊर्जा में, 1.964 करोड़ डॉलर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेअर में, 1.115 करोड़ डॉलर होटल तथा पर्यटन में 87.3 लाख डॉलर इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में, 79.9 लाख डॉलर खुदरा व्यापार में, 76.7 लाख डॉलर वस्त्र उद्योग में, 68.4 लाख डॉलर सूचना प्रसारण में, जिसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है, 13.6 लाख डॉलर हवाई यातायात में तथा 11.4 लाख डॉलर रेलवे से सम्बंधित सामानों में। फिर भी, भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाले देशों में चीन दूर-दूर तक नहीं है। भारत में कुल 50 अरब डॉलर का निवेश हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2020 में 1,03,6000 करोड़ रु. का सर्वाधिक निवेश सिंगापुर ने किया है तथा इसके बाद मॉरीशस का स्थान है जिसने भारत में 57,700 करोड़ रु. का निवेश किया है।

सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम की शेष कड़ियों के प्रसारण पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस शो के जरिये मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है

- कोर्ट ने सुदर्शन टीवी चैनल पर प्रसारित किये जा रहे उस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें सिविल सेवाओं में मुसलमानों के चयन को लेकर आक्षेप किया गया था।
- न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने कहा कि हमें इस पर बहस करने की आवश्यकता है कि क्या दूसरे लोगों को केवल एंकर के खिलाफ बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन टीवी पर यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम के शेष पांच कड़ियों के प्रसारण पर मंगलवार को यह कहते हुए रोक लगा दी कि ऐसा लगता है कि शो के जरिए मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, हमने सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल कार्यक्रम के शेष कड़ियों के प्रसारण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने सुदर्शन टीवी चैनल पर प्रसारित किये जा रहे उस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें सिविल सेवाओं में मुसलमानों के चयन को लेकर आक्षेप किया गया था।

न्यायालय ने टीवी चैनल पर कार्यक्रम दिखाए जाने के तौर-तरीके पर भी नाराजगी जतायी।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने कहा कि हमें इस पर बहस करने की आवश्यकता है कि क्या औरों को केवल एंकर के खिलाफ बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा, हम गुरुवार को नागरिकों के हर वर्ग के लिए समानता और निष्पक्षता के अधिकार तथा संवैधानिक मूल्यों के संतुलन से संबंधित मामले पर विचार करेंगे।

पायलट की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पाण्डे अत्यधिक पक्षपातपूर्ण महासचिव के रुप में सामने आये थे। वे गहलोत के निकटवर्ती माने जाते थे तथा उनकी बातों को यथावत स्वीकार कर लेते थे।

अजय माकन को एक ऐसे निष्पक्ष महासचिव की तरह व्यवहार करने की जरुरत होगी, जो सभी वर्गों और गुटों तथा सभी प्रकार के विचारों को साथ लेकर चले। यह भी समझा जाता है कि अजय माकन से कह दिया गया है कि उन्हें उन सब वादों को पूरा करना है जो राहुल तथा प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से किये हैं। उनसे यह भी कह दिया गया है कि अगर राज्य के सभी कांग्रेसजनों, भले ही वे किसी भी गुट से सम्बंधित हों, के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया तथा उन्हें समान अवसर नहीं दिये गये तो पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायेगी।

सूत्रों का कहना है कि पहली प्राथमिकता, विधायकों को विभिन्न बोर्डों का अध्यक्ष बनाये जाने तथा शेष विधायकों को पी.सी.सी. में लाये जाने की रहेगी। पायलट विधायकों को मंत्री पद दिये जाने तथा उन्हें पी.सी.सी. में तथा बोर्डों में समायोजित किये जाने, तथा निष्पक्ष व्यवहार किये जाने के लिये कह रहे हैं, जैसा कि प्रियंका तथा राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था।

क्या गुजरात...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- आश्चर्य की बात यह है कि, एन.डी.ए. बिहार में काफी सुदृढ़ है, अतः इस प्रकार के हथकण्डे अख्तियार करने की कोई जरूरत नहीं है। पर शायद एन.डी.ए. कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता।

उठाना चाहते। प्रधानमंत्री ने आज बिहार के लिए 541 करोड़ रुपयों के सात अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स की घोषणा की। इनमें से चार जलापूर्ति, दो सीवरेज ट्रीटमैंट और एक नदी तट विकास से संबंधित है। इस माह की शुरुआत में मोदी ने पी.एम. मत्स्य सम्पदा योजना, ई-गोशाला ऐप और मत्स्य उद्योग, डेयरी, बागवानी और कृषि संबंधित अन्य योजनाएं शुरु की थीं।गत 13 सितंबर को प्रधानमंत्री ने बिहार के तीन पैट्रोलियम सैक्टर प्रोजैक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित किया था। इन प्रोजैक्ट्स में एक गैस पाइप लाइन की वृद्धि करना और दो एल.पी.जी. बोटलिंग प्लांट्स शामिल थे। इसके एक दिन पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की थी कि "छठ" के त्योहार से पूर्व उत्तरी बिहार के दरभंगा से नियमित उड़ाने शुरू हो जाएंगी।

ये घटनाक्रम उन दिनों की बखूबी याद दिलाते हैं जब वर्ष 2017 में गुजरात विधानसभा चुनावों से पूर्व एक के बाद एक प्रोजैक्ट्स की घोषणा की गई थी। तब चुनाव आचार संहिता के अस्तित्व में आने से पूर्व प्रधानमंत्री ने एक पुल की आधारशिला रखी थी, अहमदाबाद राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन करने की घोषणा की थी और इस प्रकार की अन्य घोषणाओं के अलावा राजकोट के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के एक प्रोजैक्ट की आधारशिला रखी थी।

भरत सिंह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि वे उस मंत्री का नाम लिखना आवश्यक नहीं समझते। साथ ही यह भी लिखा कि गंदगी की बदबू नजदीक के लोगों को ज्यादा दुर्गंध देती है। इसी पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रभार बदलने का कितना लाभ होगा इसको परखने में समय लगेगा।

'फिल्म ''नकारा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में संदेश भिजवाने के लिए कृपया बर्खास्त करें।

एक बार पहले मुख्यमंत्री रहते आप उनको हटा चुके हैं। यह मंत्री भ्रष्टाचार के माफिया हैं। इनका नाम लिखना आवश्यक नहीं समझता हूं। गंदगी की बदबू नजदीक के लोगों को ज्यादा दुर्गंध देती है।

रक्षा मंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चलते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने-सामने की झड़प होती है।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जिस समय क्षेत्र के कमांडरों की ओर से स्थिति को सुलझाने का कार्य किया जा रहा था उस समय भी मई के मध्य में पश्चिमी क्षेत्र के अन्य हिस्से में चीन द्वारा एल.ए.सी. पार करने के अनेक प्रयास किए गए थे।

डोभाल ने मॉस्को में एससीओ शिखर बैठक का बहिष्कार किया

डोभाल बैठक में पाकिस्तान की ओर से अवैध मानचित्र पेश किये जाने का विरोध जता रहे थे

- भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी पक्ष बैठक को गुमराह करने वाली बातें करता रहा। राजनयिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की इस हरकत से रूस भी हतप्रभ रह गया। सूत्रों के अनुसार मानचित्र में भारतीय भूभाग को पाकिस्तान का क्षेत्र दिखाया जाना एससीओ घोषणापत्र का घोर उल्लंघन है।
- रूस ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पाकिस्तान की इस हरकत का कतई समर्थन नहीं करता है और उम्मीद जतायी कि पाक की इस हरकत से एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रभावित नहीं होगी।

मास्को/नई दिल्ली, 15 सितंबर (वार्ता)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस की अध्यक्षता में मास्को में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की शिखर बैठक में पाकिस्तान द्वारा भारतीय भूभाग को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र दर्शाये जाने पर कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए आज बैठक का बहिष्कार किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बदनीयती से वह काल्पनिक मानचित्र पेश किया जो उसने कुछ दिन पहले आधिकारिक तौर पर जारी किया है।

यह मेज़बान द्वारा जारी परामर्श का घोर असम्मान और बैठक के नियमों का उल्लंघन था। भारतीय पक्ष उसी समय मेजबान से परामर्श करके बैठक से उठकर निकल गया।

प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी पक्ष बैठक को गुमराह करने वाली बातें करता रहा। राजनयिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की इस हरकत से रूस भी हतप्रभ रह गया। सूत्रों के अनुसार मानचित्र में भारतीय भूभाग को पाकिस्तान का क्षेत्र दिखाया जाना एससीओ घोषणापत्र का घोर उल्लंघन है और एससीओ सदस्य देशों की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के स्थापित मानदंडों के विरुद्ध है।

सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष द्वारा पाकिस्तानी पक्ष के अवैध मानचित्र दिखाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई। रूसी पक्ष ने भी पाकिस्तानी पक्ष को ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की। रूस ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पाकिस्तान की इस हरकत का कतई समर्थन नहीं करता है और उम्मीद जतायी कि पाकिस्तान की इस हरकत से एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रभावित नहीं होगी।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः 0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908